

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-- खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ः 100

नई दिल्ली, शकवार, जन 5, 1970/ज्ये रठ 15, 1892

No. 190)

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1970/JYAISTHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सकें

Separate paging is given to this Part in ord r that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

RESOLUTION

New Delhi, the 4th June 1970

- No. F. 7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to make the following amendments to the Resolution No. F 7(25)-E.III(A)/69 dated the 23rd April 1970, setting up the Pay Commission
- 2. For the existing sub-para (vii) of para 2, the following shall be substituted, namely:—
 - (vii) having regard to all relevant factors, the Commission may, while enquiring into the level of minimum remuneration, examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage, which is based on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference.
 - 3. For the existing para 4, the following shall be substituted, namely:
 - 4. In case the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

बिस मंत्राला

सं कल्प

नई दिल्ली, 4 जून, 1970

सं० फा० 7(25)—ई III(v)/69.—चेतन श्रायोग की नियुक्ति से सम्बन्धित, 23 अर्थेल 1970 के संकल्प सं० फा० 7(25)—ई III(v)/69 में भारत सरकार ने निम्नलिखित संगोधन करने का निर्णय किया है :

- 2: पैंशाप्राफ 2 के त्रिधमान उप-पैंशाप्राफ $({\bf Vii})$ के स्थान पर निम्नलिखिन प्रतिस्थापित किया जायगा:---
 - (Vii) स्पृततम पारिश्रमिक स्तर सम्बन्धी जांच करते समय, सभी संगत तथ्य को ध्यान में रखते हुए, श्रायोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, आषण्यकता पर श्राधारित न्यूनतम वेतन की मांग की जांच कर मकता है, जो 15वे भारतीय अम सम्मेलन की सिफारिजों पर श्राधारित है।
 - विद्यमान पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :---
 - 4. भायोग के विचार विमर्ग के दौरान यदि अन्तरिम किस्म की राहत पर विचार करने की भ्रावश्यकता महसूस की जाय तो भायोग अन्तरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है और उस पर रिपोर्ट भेज सकता है। यदि श्रायोग किसी अन्तरिम राहत की सिफारिश करे तो वह यह सुझाव भी देगा कि उक्त राहत किस तारीख से दी जाय।

श्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाय । यह श्रादेश भी दिया जाता है कि इस संपल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागां, राज्य सरकारों/संव राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों श्रीर भ्रम्य सभी सम्वन्धित व्यक्तियों को भेजी जांय ।

> पी० गोविन्दन् नायर, सचिव, भारत सरकार ।